उत्तर प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रों की चीनी मिलों को दे सकती है चेतावनी

बकाया चुकाने का बढ़ेगा दबाव

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 22 मई

मौजूदा पेराई सीजन में उत्तर प्रदेश का गन्ना बकाया करीब 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की वजह से योगी आदित्यनाथ सरकार निजी क्षेत्र की मिलों पर बकाया चुकता करने का दबाव डाल सकती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्रों की मिलों पर लगभग 32,000 करोड़ रुपये के कुल बकाये में से मिलों ने अब तक 21,000 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक का भुगतान किया है। इस प्रकार शुद्ध भुगतान अनुपात मोटे तौर पर 65 प्रतिशत बैठता है जबकि पेराई सीजन खत्म होने को है।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान गन्ना बकाया विपक्षी दलों के राजनीतिक एजेंडा में सर्वोपरि था ताकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को किसान विरोधी स्वरूप में दिखाकर घेरा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव तक गन्ने का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना चुनाव से पहले भाजपा के वादों में प्रमुख रूप से शामिल था। हालांकि गन्ने की कीमतों का शीघ्र भुगतान इस दो साल पुरानी भाजपा सरकार के हाथों से फिसल गया है।

कल शाम मुख्यमंत्री को गन्ना भुगतान की स्थिति के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित करनी थी। हालांकि अंतिम समय पर बैठक स्थगित कर दी गई और अब यह बैठक एक-दो दिन में आयोजित होने की संभावना है। चूंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आए हैं और लंबित कार्यों का जायजा ले रहे हैं।

इस बीच उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि बफर स्टॉक और चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार की निर्यात सहायता योजना आदि से संबंधित किसानों के बैंक खातों में करीब 1,500 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाने की संभावना है। इससे बकाया भुगतान की स्थिति में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, 'मौजूदा सीजन का 66 प्रतिशत भुगतान अनुपात पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक है। हम पहले ही निजी मिलों की कड़ाई से जांच कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका बकाया भुगतान हो सके।'

पिछले साल आदित्यनाथ सरकार ने दबावग्रस्त निजी मिलों के लिए एक आसान ऋण योजना भी शुरू की थी। यह उन मिलों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी जिनका भुगतान अनुपात 2017-18 सीजन के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक था। बाद में उपयुक्त इकाइयों को 2,900 करोड़ रुपये से कुछ अधिक का आसान ऋण मंजूर किया गया था।

2018-19 के मौजूदा पेराई चरण में 94 निजी मिलों, 24 सहकारी मिलों और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की एक इकाई सहित कुल 119 चीनी मिलों ने पेराई परिचालन में भाग लिया था। अधिकांश मिलें अब अपना सीजन पूरा कर चुकी हैं।

पिछले साल उत्तर प्रदेश की मिलों ने सामूहिक रूप से 1.2 करोड़ टन से ज्यादा चीनी उत्पादन किया था जबकि किसानों को किया जाने वाला कुल भुगतान 35,400 करोड़ रुपये बैठता है। इस साल चीनी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कुछ कम रहने के आसार हैं। किसानों को किया जाने वाला कुल भुगतान भी 35,000 करोड़ रुपये से कम रहने की संभावना है। भूसरेड्डी ने कहा कि इस साल चीनी प्राप्ति का अनुपात ज्यादा है। इस तरह गन्ना पेराई की मात्रा भी पिछले साल की तुलना में कम रहेगी।

मिलों पर कई करोड़ रुपये बकाया

- **1,500** करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जल्द हस्तांतरित होने के आसार
- गन्ना किसानों की बकाया राशि को ध्यान में रखकर मिलों पर भुगतान का दबाव डाल सकती है योगी सरकार
- लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों के राजनीतिक एजेंडा में सर्वोपरी था गन्ना बकाया
- गन्ना भुगतान की स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री नहीं कर पाए थे समीक्षा बैठक
- अब यह बैठक एक-दो दिन में आयोजित होने की है संभावना

Business Standard
23/5/2019